Testwale Current Affairs PDF

Current Affairs search results for tag: national

1. [illegible] (Dec. 6, 2021)

2019-2021 [illegible] (NFHS) [illegible] 5 [illegible], NFHS-4 (2015-2016) [illegible] 6 [illegible] 59 [illegible]

[illegible]:

- [illegible] -5 (2019-21) [illegible] -4 (2015-16) [illegible] 8.5% [illegible] -3 (2005-2006) [illegible]
- 36 [illegible] 30 [illegible] 6-59 [illegible]
- [illegible] (79.7%) [illegible]

[illegible]-5 . [illegible] 6-59 [illegible]

[illegible] - 92.5%

[illegible] - 72.7%

[illegible] - 71.5%

[illegible] - 66.4%

[illegible] - 79.7%

[illegible] - 69.4%

[illegible] - 39.4%

[illegible] 57.4%

[illegible]:-

[illegible]

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित एक देशव्यापी सर्वेक्षण है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

2. बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस जैसलमेर में आयोजित (Dec. 6, 2021)

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री **श्री अमित शाह** ने **राजस्थान के जैसलमेर** में सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया।
- इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि **1965 में बीएसएफ की स्थापना** के बाद पहली बार मोदी सरकार ने सीमावर्ती जिले में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाने का फैसला किया है।
- 1965 के युद्ध के बाद बीएसएफ बनाने का निर्णय लिया गया था और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है।

3. भारत-मालदीव सैन्य अभ्यास (Dec. 6, 2021)

भारत और मालदीव के बीच **एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कढ़धू द्वीप** में आयोजित किया जाएगा।

- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को भूमि और समुद्र दोनों स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्रवाई आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर-संचालन में वृद्धि होगी।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान कड़े प्रशिक्षण के अलावा, रक्षा सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां भी आयोजित होंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

4. भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन (Dec. 6, 2021)

हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने **धवन 1** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित, पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बन गया।

क्रायोजेनिक इंजन का नाम इसरो के **तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर** रखा गया है। उन्होंने भारत की उन्नत अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमताओं के विकास में प्रमुख योगदान था।

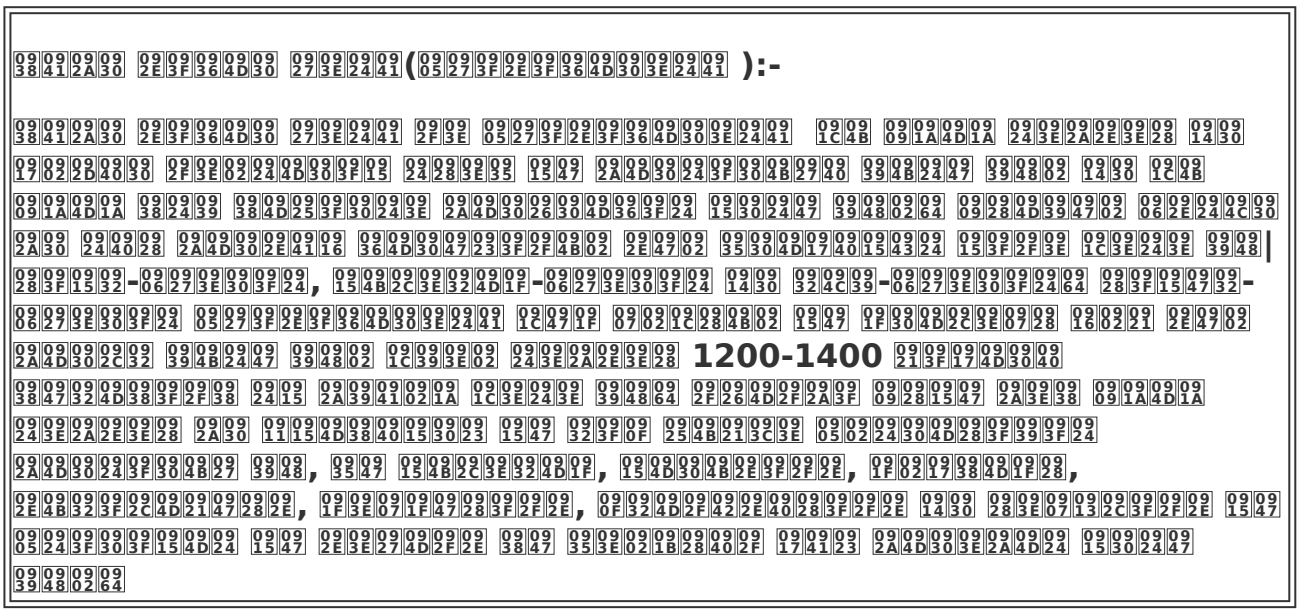

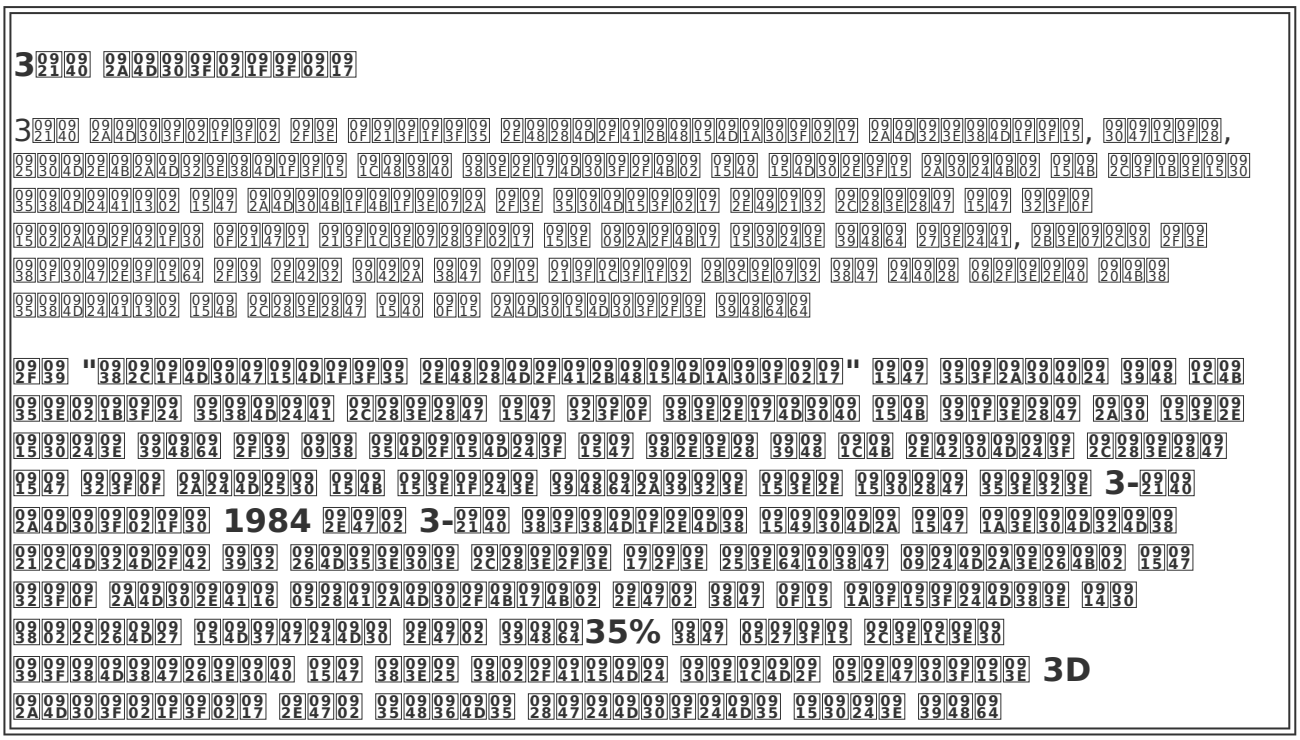

5. [illegible] **: (Dec. 5, 2021)**

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]:-

- [illegible] 1919 [illegible] 1921 [illegible]
- **[illegible]**
- [illegible]
- [illegible] 22 [illegible], 15 [illegible] 7 [illegible]
- [illegible]

[illegible]:-

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]:

- [illegible]
- [illegible]

6. [illegible] (Dec. 4, 2021)

[illegible] 2021 [illegible] 2021 [illegible] 2021 [illegible] 14 [illegible] 2021 [illegible]

- [illegible]

[illegible] 2021:-

- [illegible] 2003 [illegible]
- 2003 [illegible] 1988 [illegible]
- 2003 [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible] 2021:-

- [illegible] 1946 [illegible]
- [illegible] (CBI) [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] (CJI) [illegible]
- [illegible]

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)

- सीबीआई (केंद्रीय सतर्कता की प्रमुख जांच एजेंसी) जिसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- यह कार्मिक विभाग ,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

भ्रष्टाचार की रोकथाम पर **संथानम समिति** (1962-1964) ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की।

सीबीआई का कार्य :-

- केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है।
- इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करता है।

सीबीआई के पास आईपीसी में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित जांच करने का अधिकार क्षेत्र है।

सीबीआई न 26 भारतीय सरकारी संगठनों में से एक है जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

मुख्यालय: सीजीओ कौम्प्लेक्स, नई दिल्ली

आदर्श वाक्य: उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता

महानिदेशक: सुबोध कुमार जायसवाल

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी जो राजस्व विभाग या वित्त मंत्रालय के तहत है।

1 मई 1956 को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए, वर्ष 1957 में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था , इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया।

प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के दो प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) और

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए)

7. [illegible] 5 [illegible] 6 [illegible] (Dec. 4, 2021)

- [illegible], [illegible]
- [illegible] 40% [illegible], [illegible] 30% [illegible]
- [illegible] 1,33,83,718 [illegible]
- [illegible](MHA) [illegible] 10,645 [illegible] (7,782), [illegible] (795),[illegible] (227), [illegible] (205), [illegible] (184),[illegible] (167) [illegible] (185) [illegible] 4177 [illegible]

8. [illegible] 25,000 [illegible] (Dec. 4, 2021)

[illegible] (2[illegible]) [illegible] 25000 [illegible]

[illegible]

[illegible] 2021-22 [illegible] 73000 [illegible]

[illegible] COVID19 [illegible] 1.1 [illegible]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना

- नरेगा अधिनियम 23 अगस्त 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह 6 फरवरी, 2006 को लागू हुआ।
- 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में एक संशोधन किया गया, जिससे अधिनियम का नाम नरेगा से बदलकर कर **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम** (एमजीएनआरईजीए) कर दिया गया।
- मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, । वर्तमान में वेतन दर लगभग 210 रुपये प्रति दिन है।
- यह अब भारत के सभी ग्रामीण जिलों में चालू है
- यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- **केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री:** गिरिराज सिंह।

9. सरकार ने एयर इंडिया के लिए मांगे 62000 करोड़ (Dec. 4, 2021)

सरकार ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश के लिए बनाई गई) को ऋण और एयर इंडिया की अन्य देनदारियों के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹62,000 करोड़ का निवेश करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है।

एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है। इस कंपनी के पास एयर इंडिया का कर्ज, देनदारियां और कुछ गैर-प्रमुख संपत्तियां जैसे भूमि और भवन (14718 करोड़ रुपये) हैं। इस कंपनी को निजीकरण से पहले एयरलाइन की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए स्थापित किया गया था।

इस 62,000 करोड़ में से 28844 करोड़ निजीकरण के बाद सरकार की शुद्ध देनदारी है जबकि शेष 33105 करोड़ में कार्यशील पूंजी और विमान ऋण, लीज रेंटल, तेल कंपनियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए ब्याज देनदारियां शामिल हैं। सरकार ने अनुदान की अनुपूरक मांग में यही प्रावधान किया है।

एयर इंडिया विनिवेश:-

25 अक्टूबर 2021 को, भारत सरकार ने टाटा समूह के साथ एयर इंडिया में अपना संपूर्ण 100% हिस्सा टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो टाटा संस प्राइवेट टाटा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

यह सौदा 18,000 करोड़ रुपये का था, जिसमें से टाटा सरकार को 2,700 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और टाटा एयर इंडिया के कर्ज के 15,300 करोड़ रुपये का अधिग्रहण करेगी।

भारत सरकार को एयर इंडिया के बाकी कर्ज को चुकाना था।

इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार लोकसभा से 63,000 रुपये मांग रही है।

विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)

- एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) एक मूल कंपनी द्वारा बनाई गई कानूनी इकाई है लेकिन एक अलग संगठन के रूप में प्रबंधित की जाती है। इसे मूल कंपनी की कुछ संपत्तियों या उपक्रमों के वित्तीय जोखिम को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनियां परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए एसपीवी बनाती हैं, परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करना आसान बनाती हैं (एयर इंडिया के विनिवेश के मामले में), परिसंपत्तियों या नए उपक्रमों के जोखिम को फैलाती हैं, या मूल कंपनी से जुड़े जोखिमों से संपत्ति की रक्षा करती हैं।
- एक अलग कंपनी के रूप में इसकी कानूनी स्थिति अपने दायित्वों को सुरक्षित बनाती है, भले ही मूल कंपनी दिवालिया हो जाए।

अनुपूरक अनुदान:-

- अनुपूरक अनुदान वह राशि है जिसकी आवश्यकता तब होती है जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है।
- ये अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति (1 अप्रैल से 31 मार्च) से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 115 पूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है।

विनियोग अधिनियम: -

- इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति प्राप्त होती है।
- संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है।
- विनियोग विधेयक को बजट प्रस्तावों और अनुदान मांगों पर मतदान पर चर्चा के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है।
- संसदीय वोट में विनियोग विधेयक की हार सरकार को आम चुनाव की ओर ले जाएगी।
- वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों को धन विधेयकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्तपोषण के प्रावधान होते हैं, जबकि विनियोग विधेयक धन की निकासी की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है।

10. बारबाडोस एक गणतंत्र राष्ट्र बना (Dec. 1, 2021)

कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र **बारबाडोस** ने **30 नवंबर** को खुद को एक **गणतंत्र घोषित किया**, जो ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की 55 वीं वर्षगांठ के साथ मनाया है।

अब लगभग 3,00,000 नागरिकों का देश एक संवैधानिक राजतंत्र नहीं रहा,और नाहीं ब्रिटेन की रानी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करेगा।

29 नवंबर को, बारबाडोस, जिसे कभी लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, उसने अपने पहले राष्ट्रपति, **सैंड्रा मेसन को शपथ दिलाई।**

हालांकि बारबाडोस राष्ट्रमंडल में बना रहेगा।

बारबाडोस की राजधानी: ब्रिजटाउन

मुद्रा: बारबाडोस डॉलर

प्रधान मंत्री: मिया मोटली

राष्ट्रमंडल राष्ट्र या राष्ट्रमंडल

- राष्ट्रमंडल राष्ट्र उन देशों का एक संघ है जिन पर कभी ब्रिटेन का शासन था। वर्तमान राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का गठन औपचारिक रूप से 1949 में लंदन घोषणा द्वारा किया गया था।
- राष्ट्रमंडल के प्रमुख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं।
- वर्तमान में भारत सहित 54 सदस्य हैं